

फर्म अहकाम  
(नियम 20)

अज अदालत राजस्थान अपील प्राधिकारी, वाइफेर

गैरीदेवी गरी,  
बनाम  
समाशम गरी,

किरम मुकदमा 226 आर.टी एक्ट

न. 40 सन् 2022

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इतिशियल्या जज

गवर्नर सार्विक  
अहकाम जी इस  
हुकम की तारीख में  
जारी हुए

03.03.2022 पत्रावली बाद जांच पेश हुई। अपीलाटिंगण के अधिवक्ता श्री हरीशम चौधरी एवं कैवियटर अधिवक्ता श्री पवन सिंहल उपस्थित। अपील राजस्थान काश्तकारी एक्ट 1956 के अन्तर्गत धारा 226 विरुद्ध निर्णय साहायक कलक्टर बायतु द्वारा राजस्थान आवेदन संख्या 01/2021 बअनवान गैरीकुमारी बनाम समाशम में पारित आदेश दिनांक 21.02.2022 के विरुद्ध पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर हो। स्थगन प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पर अधिवक्ता अपीलाट की एकतरफा बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलाट ने स्थगन प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन आराजी पैतृक संपत्ति है। अपीलाधीन आराजी कंठशराम की पैतृक संपत्ति है कंठशराम के जीवनकाल में प्रार्थीगण जन्म लेकर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 व 8 के अनुसार कानूनन जन्म से ही खातेदारी अधिकार उत्पन्न हो जाने से प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया दावा स्पष्ट व गजबूत है। मूल दावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उभयपक्ष के हितों का निर्धारण मूल दावे के निस्तारण पर ही संभव है। दावे के विचाराधीन रहते अपीलाधीन आराजी का बेचान किया जाता है तो अपीलाटिंगण के दावे का औचित्य ही खत्म हो जायेगा। अपीलाटिंगण को रैसपोडेण्टिंगण अपीलाधीन आराजी से जबरन बँदखल करने पर प्रयासरत है तथा अपीलाट को अपने हिसरे की भूमि पर कब्जा काश्त में दखलवाजी कर रहे है तथा रैसपोडेण्टिंगण द्वारा अपीलाट के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप किया जा रहा है जिससे अपीलाट को भारी अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में किया जाना संभव नहीं है। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन अपीलाटिंगण के पक्ष में है। अतः अपीलाटिंगण का स्थगन प्रार्थना-पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

कैवियटर अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन आराजी का बेचान मुझ रैसपोडेण्टरा के पक्ष में हस्तगत दावा पेश होने से पूर्ण ही बेचान किया गया। रैसपोडेण्टरा अपीलाधीन आराजी के शक्यापी क्रेता है। क्रयशुवा भूमि पर रैसपोडेण्टरा का कब्जा काश्त है। अपीलाटिंगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन रैसपोडेण्टरा के पक्ष में है। अतः स्थगन प्रार्थना-पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि रैसपोडेण्ट संख्या 01 ने अपीलाधीन आराजी का बेचान रैसपोडेण्ट संख्या 06 से 08 के पक्ष में दावा पेश होने से पूर्ण में ही

राजस्थान अपील प्राधिकारी  
वाइफेर

किया गया। मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उभयपक्षकारान के हकों का निर्धारण मूल वाद के निस्तारण पर ही संभव है। रैस्पोंडेंटगण द्वारा अपीलाधीन आदेश की आड़ में अपीलांटगण के कब्जे काशत में हस्तक्षेप करते हैं तो अपीलांटगण के हितों पर कूठाराघात संग्राह्य है। प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः अपील एडमिशन स्टेज पर आंशिक स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.02.2022 में संशोधन करते हुए आदेश दिये जाते हैं कि जमावंदी मौजा केरलीनाडी पटवार गण्डल नौसर तहसील बायतु के खसरा संख्या 34 रकबा 0.0324 हैक्टयर व खसरा संख्या 634/35 रकबा 42.9822 हैक्टयर भूमि में प्रक्रियाधीन नामान्तरकरण को स्वीकृत करने के आदेश दिये जाते हैं तथा उसके पश्चात व्यर्थ ही मुकदमेवाजी नहीं बढे इसलिए उपरोक्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड की यथारिथति बनाये रखने के आदेश दिये जाते हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित शेष स्थगन आदेश यथावत रहेगा। अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि हस्तगत आवेदन में समुचित सुनवाई करते हुए अधिकतम दो माह में निस्तारण करे। पत्रावली फैंशल शुमार नंबर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे इजलाश सुनाया गया।

  
राजस्व अपील अधिकारी  
बाइमेर